NEWS PAPER CLIPPINGS

Name of News Paper: The Indian Express

Dated: February 15, 2011

Nitish Kumar may face tough questions from the Commission at Bihar's Annual Plan meeting today

Plan panel says, Bihar missing targets

PRIYADARSHI SIDDHANTA
NEW DELHI, FEBRUARY 14

THE Planning Commission is upset with the Nitish Kumar government in Bihar for not doing enough to achieve all-round development of the state. The commission believes that the JD(U)-ruled regime needs to generate rural employment, promote industry and ensure nutritional care of the school children on a faster pace to match the national indicators.

Kumar may have to explain to the Commission when he meets its top brass to discuss Bihar's Annual Plan for 2011-12 here tomorrow as to why his state was lagging behind national indicators. To begin with, the plan panel is upset that poverty level of the state is much higher than the national average in both urban and rural areas. A top Commission told *The Indian Express* that compared to the all India work average of 28.3 per cent and 25.7 per cent for rural and urban areas respectively, Bihar's figures of 42.1 per cent and 34.6 per cent was worrying. "It implies that the state will have to accord top priority to creating livelihood opportunities," he said.

Similarly, the state's performance on the flagship Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme wasn't encouraging either. In fact, the Commission was worried that the average percentage per household of work generated when compared with the national average has fallen during the past four fiscals (2007-08 to 2010-11). Its utilisation of available funds was inadequate, he said. According to the Centre's data, the state was earmarked Rs 2,213.59 crore, while it has been able to utilise Rs 1,816.88 crore. Moreover only 0.02 per cent work have been completed against 1,88,551 projects taken up by the state.

Bihar chief minister Nitish Kumar with Narendra Jadhav, member of Planning Commission, at Janata Darbar in Patna on Monday. PTI

The panel believes that Bihar's Industrial Policy unveiled in 2006 was skewed towards dependence on providing fiscal incentives in the forms of subsidy and concessions for attracting investments. "This is contrary to the policies being pursued by the Centre, which emphasizes for creation of enabling conditions and removal of impediments, which raise transaction costs," the official said pointing out that they would expect Kumar to outline steps his administration has taken to come up with a Comprehensive State Manufacturing Competitiveness Report to identify sectors, which have potential endowment in Bihar.

On the Mid-Day Meal scheme, Bihar has not incurred any expenditure in monitoring it, while districts like Bhojpur, Nalanda, East Champaran, Jamui and Rohtas have huge stock foodgrains lying unutilised. On the health front, Bihar has higher crude birth rate and infant mortality rate compared to the national average and the state was likely to miss the 11th Plan targets. "The health scenario in Bihar could be gauged from the fact that 1,243 of 1,776 primary health care centres are without doctors," the official said.

NEWS PAPER CLIPPINGS

Name of News Paper: Hindustan

Dated: 14/2/2011

कम नहीं होगा योजना आकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना आयोग की टीम से साफ कहा, राज्य का योजना आकार 24 हजार करोड़ का ही हो

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

राज्य के योजना आकार को हर हाल में 24 हजार करोड़ रखने पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना आयोग से योजनाओं के चयन और स्वीकृति में राज्यों को और स्वतंत्रता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में आयोग बिहार को विशेष योजना से 3145 करोड़ रुपये दे। साथ ही बिहार में बीपीएल के चयन के लिए भारत सरकार स्वतंत्र आयोग का गठन करे।

बिहार मॉडल की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सामान खरीदकर देने के बदले लाभार्थियों को सार्वजनिक सभा में नगद राशि देनी चाहिए। योजना आयोग के सदस्य नरेन्द्र जाधव ने रविवार को मुख्यमंत्री के साथ योजना आकार से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में योजना आयोग के सदस्य ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी यहां काम हो रहा है। ऐसे में योजना आकार में वृद्धि होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि योजना आयोग राज्य सरकार को अधिक स्वतंत्रता दे ताकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई सलाह भी दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए लाभार्थियों को खाद्यान्न के बदले नगद भुगतान किया जाए। साइकिल योजना को उदाहरण के तौर पर रखते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल खरीदकर देने के बदले नगद राशि ही दी जा रही है।

जाधव ने बिहार में लागू किए जा रहे

विचार-विमर्श

- योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने पर सीएम का बल
- बिहार मॉडल का दूसरे राज्य भी करें अनुकरण: जाधव
- योजना आयोग के सदस्य ने किया मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श

सीएम की मांग

- योजनाओं के चयन में राज्यों को मिले स्वतंत्रता
- बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में बिहार को मिले 3145 करोड़ रुपये
- बीपीएल के चयन के लिए केंद्र स्वतंत्र आयोग का गठन करे
- लाभार्थियों को सार्वजनिक सभा में नगद राशि दी जाए

योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि अब बिहार मॉडल के रूप में जाना जाता है। महादलितों को दी जा रही तीन डिसमिल जमीन की योजना की भी उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने बिहार में सौर और वायु ऊर्जा के सम्मिलित संयंत्र लगाने की सलाह दी। 15 फरवरी को दिल्ली में योजना आयोग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही 15 विभागों के प्रधान सचिव भी हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य सचिव अनुप मुखर्जी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश, विकास आयुक्त के.सी.साहा, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, एस.सिद्धार्थ एवं अतीश चंद्रा उपस्थित थे।

(संबंधित फोटो पेज-2 पर)

NEWS PAPER CLIPPINGS

Name of News Paper : Hindustan

Dated: 14/2/11

रविवार को संवाद कक्ष में योजना आयोग के सदस्य नरेन्द्र जाधव व पदाधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

दैनिक जागरण 25.2.11

फूल सिंह ने दी समाज को नई दिशा : आशा

शहीद भक्त फूल सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री की पत्नी आशा हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित करती हुईं। जागरण

गोहाना, संवाद सहयोगी : हरियाणा बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष आश हुड्डा ने कहा कि अमर शहीद भक्त फूल सिंह ने विषम परिस्थितियों में महिला वर्ग के अंदर शिक्षा की नई किरण जगाने का काम किया है। भक्त फूल सिंह ने उस समय महिलाओं को शिक्षित करने की शुरुआत की जब महिलाओं को घरों की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता था। वह बृहस्पतिवार को भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में शहीद भक्त फूल सिंह की 126वीं जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार रख रही थी।

आशा हुड्डा ने कहा कि 1936 में शहीद भक्त फूल सिंह खानपुर कन्या गुरुकुल की नींव रखी थी। उन्होंने तीन छात्राओं से एक गुरुकुल को शुरू किया था। हुड्डा ने कहा कि शहीद भक्त फूल सिंह ने समाज को नई दिशा दी। प्रदेश सरकार ने भी भक्त फूल सिंह के सपनों को साकार करने के लिए

समारोह

- हरियाणा बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष आश हुड्डा ने किया संबोधित

गुरुकुल संस्थाओं को महिला विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि महिला विश्वविद्यालय अब नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने छात्राओं को प्रतिस्पर्धा के युग में आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने को कहा। इस मौके पर भारत में उच्चतर शिक्षा-विजन 2020 विषय पर योजना अयोग के सदस्य डा. नरेंद ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2050 में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सरताज होगा। इस मौके पर विधायक जगबीर सिंह मलिक भी मौजूद थे।

Name of News Paper: Danik Jagran

Dated: 14/2/11

नीतीश ने मांगा बिहार का हक

पटना, जागरण ब्यूरो : योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव बिहार के विकास से प्रभावित हैं। उनके अनुसार दूसरे राज्यों को भी बिहार माडल अपनाना चाहिये। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे बिहार का योजना आकार 24 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत करने की बात कही। मुख्यमंत्री का जोर रहा कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार एक स्वतंत्र आयोग का गठन करे।

मुख्यमंत्री के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए लाभार्थियों को खाद्यान्न देने के बदले नकद भुगतान किया जाये। उन्होंने बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड की चर्चा करते हुए कहा कि विशेष योजनाओं के लिए इस मद में 3145 करोड़ रुपये बिहार को दिए जाएं। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं को स्वीकृति देने में योजना आयोग राज्य सरकार को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे, ताकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया ■ शेष पृष्ठ 19 पर

योजना आयोग के सदस्य से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जागरण

मुलाकात

- दूसरे राज्य भी अपनाएं बिहार माडल : मुख्यमंत्री
- योजना आयोग के सदस्य ने सीएम से की मुलाकात
- बोले–बीपीएल में चयन को केंद्र बनाये स्वतंत्र आयोग

नीतीश ने मांगा बिहार का हक

कि लाभार्थियों को सामग्री देने की जगह नगद भुगतान हो। नगद राशि का वितरण सार्वजनिक सभा कर जनप्रतिनिधियों के समक्ष दिया जाये। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। यह बिहार माडल है।

योजना आयोग के सदस्य श्री जाधव ने कहा कि बिहार में हो रहे प्रयोग यानी बिहार माडल को दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम की खूब सराहना की। बिहार में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने यह परामर्श दिया कि सौर ऊर्जा व बायो ऊर्जा का संयंत्र पायलट परियोजना के तहत लगाया जाना चाहिए। मार्च के पहले हफ्ते में इस तकनीक की प्रस्तुति पटना में की जायेगी। योजना आयोग के सदस्य के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात के अवसर पर मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी, विकास आयुक्त, केसी साहा, योजना विभाग के प्रधान सचिव, विजय प्रकाश व वित्त विभाग के प्रधान सचिव, रामेश्वर सिंह भी मौजूद थे।